मनोहर लाल शर्मा

बनाम

प्रिंसीपल सैक्रेटरी एवं अन्य

(रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 120/2012)

सितंबर 24,2014

[आर. एम. लोधा, सीजेआई, मदन बी. लोकुर और कुरियन जोसेफ, न्यायाधिपतिगण]

कोयला - कोयला ब्लॉकों का आवंटन- का रद्द करना - भारत सरकार की स्क्रीनिंग कमेटी और सरकारी वितरण मार्ग द्वारा किए गए कोयला ब्लॉकों के आवंटन को मनमाना और अवैध ठहराया गया - ऐसे रद्दीकरण के परिणाम - भारत संघ द्वारा इस आशय का शपथ पत्र कि कोयला वास्तव में कहाँ से खनन किया गया है हलफनामे के अनुबंध I में सूचीबद्ध 40 कोयला ब्लॉक और अनुबंध II में सूचीबद्ध 6 कोयला ब्लॉक निष्कर्षण के लिए तैयार हैं - मुद्दा यह है कि इन कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द किया जाना है या नहीं– : आवंटन की प्रक्रिया को एक समिति की नियुक्ति के माध्यम से संपार्श्विक रूप से फिर से नहीं खोला जा सकता है , क्योंकि यह वास्तव में निर्णय को रद्द करने के समान होगा - प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना वाले सभी पक्षों को सुनवाई का मौका दिया गया था, इस प्रकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को लागू किया गया था - आवंटन की पहली श्रेणी अनुलंग्नक 1 और अनुलंग्नक 2 में उल्लिखित के अलावा अन्य हैं जो अवैध और मनमाने हैं, आवंटियों ने अभी तक कोई खनन पट्टा नहीं लिया है और उन्होंने अभी तक उत्पादन शुरू नहीं किया है, इस प्रकार, ये सभी आवंटन रद्द कर दिए जाते हैं - दूसरी श्रेणी अनुलग्नक 1 और अनुलग्नक 2 में उल्लिखित 46 कोयला ब्लॉक हैं, हालांकि उत्पादन शुरू कर चुके

हैं या उत्पादन शुरू करने के कगार पर हैं - ये आवंटन अवैध और मनमाने हैं, इसलिए रद्द किए जा सकते हैं - हालांकि, मोहेर और मोहेर अमरोली एक्सटेंशन को कोयला खंडो का आवटन, सासन पावर लिमिटेड (यूएमपीपी) तसरा (स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया सेल को आवंटित) और पाकरी बरवाडीह कोयला ब्लॉक (नेशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी को आवंटित), रद्द होने के लिए उत्तरदायी नहीं है – रद्दीकरण 31 मार्च, 2015 से प्रभावी होगा – 6 महीने की अवधि दी जा रही है क्योंकि केंद्र सरकार और सीआईएल को बदली हुई स्थिति को समायोजित करने और आगे बढ़ने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी और साथ ही कोयला ब्लॉक आवंटियों को अपने मामलों को समायोजित करने और प्रबंधित करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है - फैसले के दायरे में आने वाले कोयला ब्लॉकों और इस आदेश के दायरे में आने वाले चार कोयला ब्लॉकों के अलावा अन्य कोयला ब्लॉकों के आवंटियों को 295/- रुपये प्रति मीट्रिक टन रुपये की राशि का भुगतान निर्धारित अवधि के भीतर निकाले गए कोयले पर अतिरिक्त लेवी का करना होगा। - इसके बाद 31 मार्च, 2015 तक निकाले गए कोयले पर भी रुपये 295/- प्रति मीट्रिक टन की अतिरिक्त लेवी लगेगी - 46 में से 12 कोयला ब्लॉकों के आवंटन के संबंध में सीबीआई द्वारा जांच जारी रहेगी।

समाज परिवर्तन समुदाय बनाम कर्नाटक राज्य आई ए. नंबर 201 और 219, 223 अंतर्गत आईए नंबर 204 एवं आई.ए. संख्या 224 अंतर्गत आई.ए. संख्या 215 अंतर्गत रिट याचिका (सिविल) संख्या 562/2009; अशोक हुर्रे बनाम रूपा अशोक हुर्रे 2002 (2) एससीआर 1006: (2002) 4 एससीसी 388; नेशनल टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन बनाम पी.आर. रामकृष्ण 1983 (1) एससीआर 922: (1983) 1 एससीसी 228; शीला बरसे बनाम भारत संघ 1988 (2) सप्ल. एससीआर 643: (1988) 4 एससीसी 226; ओंकार लाल बजाज बनाम भारत संघ 2002 (5) सप्ल. एससीआर 605 :

(2003) 2 एससीसी 673; चिंगलपुट बॉटलर्स बनाम मैजेस्टिक बॉटलिंग कंपनी 1984 (3) एससीआर 190: एआईआर 1984 एससी 1030 – संदर्भित किया गया ।

केस कानून संदर्भ:

2002 (2) एससीआर 1006	संदर्भित किया गया	पैरा 16
1983 (1) एससीआर 922	संदर्भित किया गया	पैरा 18
1988 (2) पूरक एससीआर 643	संदर्भित किया गया	पैरा 20
2002 (5) पूरक एससीआर 605	संदर्भित किया गया	पैरा 21
1984 (3) एससीआर 190	संदर्भित किया गया	पैरा 22

आपराधिक मूल क्षेत्राधिकार : रिट याचिका (आपराधिक) 120/2012

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

मय

डब्ल्यू. पी. (सिविल) 463 और 515 / 2012

डब्ल्यू. पी. (सिविल) 283 / 2013

मनोहर लाल शर्मा (व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता), समन, प्रशांत भूषण, प्रणव सचदेवा, सत्यजीत देसाई, अक्षय एम. सुदामे, अनघा एस. देसाई, ज्योति मेंदिरत्ता; याचिकाकर्ता के लिये।

मुकुल रोहतगी, एजी., रंजीत कुमार, एसजी., मनिंदर सिंह, एएसजी., ए. सरन, अनिल बी. दीवान, के.के. वेणुगोपाल, रवेन्द्र श्रीवास्तव, के.वी. विश्वनाथन, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, हरीश एन. साल्वे, दुष्यन्त दवे, कृष्णन वेणुगोपाल, पारस कुहाड़, गोपाल जैन, राकेश द्विवेदी, अजीत कुमार सिन्हा, विकास सिंह, डॉ. राजीव धवन,

टी.आर. अंध्यारुजिना, गोपाल जियान, अरिजीत प्रसाद, बीनू टम्टा, सुषमा सूरी, डी.एस. माहरा, अमित आनंद तिवारी, संचित गुरु, आशुतोष झा, अविनाश त्रिपाठी, रमेश बाबू एम.आर., अनिप सच्ते, मोहित पॉल, शगुन मट्टा, साकार सरदाना, अपूर्व कुरूप, प्रशांतो सेन, सी.डी. सिंह, राठी रोहित, वी.सी. शुक्ला, साक्षी कक्कड़, संजीव के. कपूर, गौरी रसगोत्रा, समन अहसन, प्रतीक कुमार, गौरव जुनेजा, रजत जरीवाल रौनक ढिल्लों, साहिल नारंग, करण खन्ना, शिखर श्रीवास्तव (खेतान एंड कंपनी के लिए), आदित्य गंजू (खेतान एंड कंपनी के लिए), महेश अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल, ई.सी. अग्रवाल, नेहा नागपाल, पारुल शुक्ला, वी. श्याम मोहन, कुरियाकोस वर्गीस, श्रेवास मेहरोत्रा, चैताली धिनोजिया, डी. महेश बाबू, निखिल नैय्यर, कीर्ति रेनू मिश्रा, तपेश कुमार सिंह, मो. वक़्वास, अपर्णा भट्ट, ममता सक्सैना, ए.एन. सिंह, तनिमा किशोर, भवानीशंकर वी. गडनीस, वरुण पाठक, रवि प्रकाश, राहील कोहली, आदित्य दीवान, रतन के. सिंह, सूरज प्रकाश, शशि भूषण, अक्षय मल्होत्रा, तुषार रॉय, रऊफ रहीम, नंदिनी गोरे, देविना सहगल, त्रिशला कुलकर्णी, माणिक करंजावाला (करंजावाला एंड कंपनी के लिए), ब्रज किशोर मिश्रा, मिश्रा सौरभ, वंशजा शुक्ला, अंकित कुमार लाल, कामिनी जयसवाल, एस. उदय कुमार सागर, हेमंतिका वाही, जेसल, प्रीति भारद्वाज, पूजा सिंह, अनुराधा दत्ता, फ़रेश्ते डी. सेठना, विजयलक्ष्मी मेनन, आकृति, तारिणी सूदन, वरुण मिश्रा, बी.आर. मेनन, पवन उपाध्याय, शर्मिला उपाध्याय, ई.आर. कुमार, शशांक, फैसल शेरवानी, अभिनय, अभिषेक देशमुख (पारेख एंड कंपनी के लिए), मीनाक्षी ग्रोवर, ऐश्वर्या सिन्हा, कुणाल वर्मा, आरोही भल्ला, आशीष बरमार्ड, सुजाता कुर्दुकर, भरत संगल, आई. अबेंला आयर, पल्लवी लंगर, तुशाल बख्शी, अनिता शेनॉय, सौमिक घोषाल, राणा मुखर्जी, नेहा शर्मा, डी. वर्मा, बी. बालाजी, आर. राकेश शर्मा, एस. आनंद, शासे, ललित भसीन, नीना गुप्ता, संजय गुप्ता, मुदित शर्मा, अमित शर्मा, दीपेश

सिन्हा, अशोक क्र. पारिया, आनंद वर्मा, धनंजय मिश्रा, रमेंद्र मोहन पटनायक, एल.के. भूषण, वैभव जोशी (दुआ एसोसिएट्स के लिए) दिनेश कुमार गर्ग प्रतिवादीण के लिए।

न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया

आदेश

1. 25 अगस्त, 2014 को इन मामलों में फैसला सुनाया गया और अन्य बातों के साथ-साथ यह माना गया कि भारत सरकार की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किए गए कोयला ब्लॉकों का आवंटन, साथ ही सरकारी वितरण मार्ग के माध्यम से किए गए आवंटन अवैध और मनमाने हैं। चूंकि जिस निष्कर्ष पर पहुंचा गया उसके संभावित रूप से दूरगामी परिणाम हो सकते थे, जिस पर मामले की सुनवाई के दौरान कोई दलील नहीं दी गई थी, घोषणा के परिणाम क्या होने चाहिए, इस सवाल को सुनवाई के लिए खुला छोड़ दिया गया था।

2. 25 अगस्त, 2014 के फैसले का संदर्भित पैराग्राफ इस प्रकार हैं:-

"155. सरकारी वितरण मार्ग के माध्यम से कोयला ब्लॉकों का आवंटन, वस्तु चाहे कितनी भी प्रशंसनीय क्यों न हो, अवैध भी है क्योंकि सीएमएन अधिनियम की योजना के अनुसार इसकी अनुमति नहीं है। कोई भी राज्य सरकार या राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वाणिज्यिक उपयोग के लिए कोयला खनन के लिए पात्र नहीं हैं। चूँकि धारा 3(3) और (4) के तहत केवल उन्हीं श्रेणियों के लिए कोयले का आवंटन अनुमेय है, अपात्र फर्मों के साथ संयुक्त उद्यम व्यवस्था भी अनुमेय है। समान रूप से, आवंटन में किसी संघ/नेता/संघ का भी कोई प्रश्न नहीं है। केवल सीएमएन अधिनियम की धारा 3(3) में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाला उपक्रम, अर्थात, जिसकी एक इकाई लौह और इस्पात के उत्पादन और बिजली उत्पादन, खदान

से प्राप्त कोयले की धुलाई या सीमेंट के उत्पादन में लगी हुई है, केंद्र सरकार के अलावा, एक केंद्र सरकार की कंपनी या एक केंद्र सरकार निगम आवंटन का हकदार है।

156. इस संदर्भ में, यह ध्यान देने योग्य है कि 1957 के अधिनियम में धारा 11-ए को 13.02.2012 से प्रभावी ढंग से शामिल करते हुए संशोधन किया गया है। उक्त संशोधन के अनुसार, कोयला या लिग्नाइट वाले क्षेत्र के संबंध में टोही परमिट या पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे का अनुदान केवल धारा 3(3)(ए)(iii), उपर संदर्भित के तहत पात्र संस्थाओं के बीच भी प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से चयन के माध्यम से किया जा सकता है। हालाँकि, सरकारी कंपनियाँ, सरकारी निगम या कंपनियाँ या निगम, जिन्हें टैरिफ (अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स सहित) के लिए प्रतिस्पर्धी बोलियों के आधार पर बिजली परियोजनाओं से सम्मानित किया गया है, उनके पक्ष में आवंटन से छूट दी गई है, इसका मतलब प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से नहीं है।

157. जैसा कि हमने पहले ही पाया है कि स्क्रीनिंग कमेटी मार्ग और सरकारी वितरण मार्ग दोनों के तहत किए गए आवंटन मनमाने और अवैध हैं, इसके परिणाम क्या होने चाहिए, यह मुद्दा है, जिससे निपटा जाना है। हमारा विचार है कि, इस सीमित सीमा तक, मामले में आगे सुनवाई की आवश्यकता है।"

3. तदनुसार, हमने बहुत बड़ी संख्या में हस्तक्षेपकर्ताओं, पक्षकार आवेदकों और राज्य सरकारों की ओर से पेश हुए कई विद्वान वकीलों को सुना। अन्य लोगों के अलावा, कोल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा महत्वपूर्ण प्रस्तुतियाँ दी गईं। 25 अगस्त, 2014 को फैसला सुनाए जाने से काफी पहले भी इन संगठनों को सुना गया था।

4. इन "परिणाम कार्यवाहियों" के प्रयोजनों के लिए, भारत संघ ने 8 सितंबर, 2014 को एक हलफनामा दायर किया। हलफनामे में कहा गया है कि कोयले का खनन वास्तव में हलफनामे के अनुबंध I में सूचीबद्ध 40 कोयला ब्लॉकों से किया जा रहा है। इस सूची में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स (सासन पावर लिमिटेड [यूएमपीपी] को मोहर और मोहर अमरोली एक्सटेंशन) को कोयला खंड आवंटित किये गये। फैसले में यूएमपीपी को आवंटित कोयला ब्लॉकों से छेड़छाड़ नहीं की गई है। 40 कोयला ब्लॉकों की सूची इस आदेश के साथ अनुबंध 1 के रूप में संलग्न है।

5. उपरोक्त 40 कोयला ब्लॉकों के अलावा, हलफनामे में कहा गया है कि 6 और कोयला ब्लॉक 2014-15 में कोयला निकालने के लिए तैयार हैं और यह सूची हलफनामे के अनुलग्नक II में है। इन 6 कोयला ब्लॉकों ने कोलियरी नियंत्रण नियम 2004[1] (खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत बनाए गए) के नियम 9 के तहत कोयला नियंत्रक संगठन से खदान खोलने की अनुमति प्राप्त की है। यह अनुमति खनन पट्टे के निष्पादन के बाद प्रदान की गई । इन 6 कोयला ब्लॉकों की सूची इस आदेश के साथ अनुबंध 2 के रूप में संलग्न है।

6. इसलिए, हलफनामा बिल्कुल स्पष्ट है कि 40 कोयला ब्लॉक पहले से ही कोयला उत्पादन कर रहे हैं और 6 कोयला ब्लॉक वस्तुतः तत्काल प्रभाव से कोयला उत्पादन करने की स्थिति में हैं। सवाल यह है कि क्या इन कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द किया जाना चाहिए या नहीं।

7. विद्वान अटॉर्नी जनरल द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि कानून की घोषणा और इस निष्कर्ष के बाद कि कोयला ब्लॉकों का आवंटन मनमाना और अवैध था, फैसले से केवल दो परिणाम सामने आए। पहला स्वाभाविक परिणाम है, यानी, कोयला ब्लॉकों का आवंटन (फैसले में उल्लिखित ब्लॉकों के अलावा) रद्द किया जाना चाहिए और केंद्र

सरकार चीजों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दूसरा विकल्प यह है कि 46 कोयला ब्लॉकों (जैसा कि ऊपर बताया गया है) को बिना किसी बाधा के (शर्तों के अधीन) छोड़ दिया जाए और शेष कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द कर दिया जाए।

8. वैकल्पिक परिणाम पर प्रकाश डालते हुए, यह प्रस्तुत किया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) इन 44 कोयला ब्लॉकों से कोयले की निकासी को अपने कब्जे में ले सकता है और उनमें कार्यरत लोगों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी रख सकता है। हालाँकि, यह प्रस्तुत किया गया था कि सीआईएल को कोयला ब्लॉकों को अपने कब्जे में लेने और खनन प्रक्रिया जारी रखने के लिए अपने मामलों का प्रबंधन करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी। प्रभावी रूप से, यह प्रस्तुत किया गया कि भले ही इन 44 कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द कर दिया जाए, केंद्र सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि कोयला उत्पादन बंद नहीं होगा।

9. लीमेड अटॉर्नी जनरल ने प्रस्तुत किया कि कोयला ब्लॉकों के सभी आवंटियों को 295/- रु प्रति मीट्रिक टन कोयला की अतिरिक्त लेवी का भुगतान करने का निर्देश अवैध और मनमाने आवंटन से सरकारी खजाने को होने वाले वित्तीय नुकसान से निपटने के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट के अनुसार निष्कर्षण की तारीख से दिया जाना चाहिए। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि बिजली क्षेत्र कोयले की आपूर्ति करने वाले आवंटियों के मामले में, उन्हें राज्य उपयोगिता या वितरण कंपनी (जैसा भी मामला हो) के साथ बिजली खरीद समझौते (पीपीए) में प्रवेश करने के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को लाभ दिया जा सके।

10. प्रचुर सावधानी बरतते हुए, विद्वान अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 6 कोयला ब्लॉकों के आवंटन के संबंध में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा एक प्रथम सूचना

रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसलिए, यह पता लगाने के लिए जांच जारी है कि क्या 6 कोयला ब्लॉकों के आवंटन के संबंध में कोई आपराधिक अपराध किया गया है। इसके अलावा, यह बताया गया है कि सीबीआई ने 3 सितंबर, 2014 को सूचित किया था कि 6 अन्य कोयला ब्लॉकों के आवंटन में किसी भी कथित आपराधिकता या अन्यथा के संबंध में अंतिम निर्णय विचाराधीन है। दूसरे शब्दों में, विद्वान अटॉर्नी जनरल द्वारा पहचाने गए 46 कोयला ब्लॉकों में से 12 के आवंटन में कथित आपराधिकता की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है।

11. अटॉर्नी जनरल के सुझावों को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, उनका सारांश नीचे दिया गया है।

(1) सभी कोयला ब्लॉक आवंटन (निर्णय में उल्लिखित को छोड़कर) रद्द किए जा सकते हैं।

(2) वैकल्पिक रूप से,

(ए) 40 कार्यात्मक और 6 "तैयार" कोयला ब्लॉकों से कोयला निकालने की अनुमति दी जा सकती है और शेष कोयला ब्लॉक रद्द कर दिए जाएंगे;

(बी) सभी 46 कोयला ब्लॉकों के आवंटियों को निष्कर्षण की तारीख से निकाले गए प्रति मीट्रिक टन कोयले पर 295/- रुपये की अतिरिक्त लेवी का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए; और

(सी) बिजली क्षेत्र के लिए कोयला ब्लॉकों के आवंटियों को राज्य उपयोगिता या वितरण कंपनी, जैसा भी मामला हो, के साथ पीपीए में प्रवेश करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

12. विद्वान अटार्नी जनरल ने दो पूरक तर्क दिये, दिए गए सुझावों से सीधे तौर पर संबंधित नहीं हैं। यह प्रस्तुत किया गया था कि हालांकि स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा और

सरकारी वितरण मार्ग के माध्यम से किए गए सभी आवंटन अवैध और मनमाने ढंग से किए गए थे, लिग्नाइट ब्लॉकों का आवंटन 25 अगस्त, 2014 को दिए गए फैसले में चर्चा का विषय नहीं था। यह सही है और यह स्पष्ट किया जाता है कि 25 अगस्त, 2014 को दिया गया निर्णय लिग्नाइट ब्लॉकों से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है और उनके आवंटन उक्त निर्णय के अंतर्गत नहीं आते हैं।

13. दूसरी बात, रुपये 295/- प्रति मीट्रिक टन अतिरिक्त लेवी के रूप में निकाले गए कोयले का आंकड़ा (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर) की गणना ओपन कास्ट खदानों और मिश्रित खदानों के आधार पर की गई है, जबकि भूमिगत खदानों को गणना में नहीं लिया गया। जिन कोयला ब्लॉकों को रद्द होने से "बचाने" की मांग की गई है, उनमें से किसी भी विद्वान वकील ने यह नहीं बताया है कि 46 कोयला ब्लॉकों में से किसी में भी भूमिगत खदान है या नहीं। इसलिए, किसी काल्पनिक मामले से निपटने का कोई अवसर नहीं है।

14. अटॉर्नी जनरल श्री के.के. की दलीलों के जवाब में, कोल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील वेणुगोपाल ने कहा कि सभी कोयला ब्लॉकों को रद्द करने के बहुत गंभीर और दूरगामी परिणाम होंगे।

15. कोयला ब्लॉकों को रद्द करने के परिणामों को श्री वेणुगोपाल द्वारा विभिन्न शीर्षकों के तहत वर्गीकृत किया गया था और इनका विवरण नीचे दिया गया है।

(1) देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा: यह प्रस्तुत किया गया कि सरकारी कंपनियां आवश्यक मात्रा में कोयले की आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं हैं; वास्तव में, दीर्घकालिक कोयला लिंकेज के लिए कोयला मंत्रालय के पास बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हैं; बिजली स्टेशनों के पास एक सप्ताह से भी कम कोयले की आपूर्ति है और इसलिए बिजली कटौती की संभावना है; कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के

लिए कोयले की आपूर्ति में कमी के कारण राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) और दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के कम से कम 10 बिजली संयंत्र बंद कर दिए गए हैं; सीआईएल द्वारा आपूर्ति किये गये कोयले की खराब गुणवत्ता का मुद्दा है; लगभग रु. 2.87 लाख करोड़ तक का भारी निवेश दिसंबर, 2012 तक 157 कोयला ब्लॉकों किया गया है; स्थाई संयंत्रो में लगभग 4 लाख करोड़ रूप्ये का निवेश किया गया है; लगभग 10 लाख लोगों का रोजगार खतरे में है; आवंटित कोयला ब्लॉक में कोयले की विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए अंतिम-उपयोग संयंत्रों को डिजाइन किया गया है और कोयला ब्लॉकों को रद्द करने के परिणामस्वरूप अंतिम-उपयोग संयंत्र निरर्थक हो जाएगा; बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा लगभग रुपये 2.5 लाख करोड़ की सीमा तक ऋण दिए गए गैर-निष्पादित परिसंपत्ति बन जाएंगे; भारतीय स्टेट बैंक को हो सकता है रूपये 78,263 करोड़ का नुकसान हो, जो वित्तीय वर्ष 2013 के लिए इसकी निवल संपत्ति का लगभग 7.9% है; पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक जैसे अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भारी झटका लगेगा; ग्रामीण बिजली निगम और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों का बैंकों से भी अधिक जोखिम है; डी-आवंटन के वैश्विक प्रभाव होंगे जैसे निवेशकों के विश्वास पर नकारात्मक प्रभाव; कुछ उद्योगों में तीव्र संकट; प्राथमिक ईंधन स्रोत के रूप में बिजली उत्पादन के लिए 60% तक कोयले पर देश की निर्भरता के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति हो सकती है; आवंटन रद्द होने से 28,000 मेगावाट बिजली क्षमता प्रभावित होगी; कोयला खदानें बंद होने से रॉयल्टी, उपकर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के मामले में अनुमानित तौर पर 4.4 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होगा; कोयला आयात (पहले से ही बहुत अधिक) वित्त वर्ष 2016-17 में और भी अधिक बढ़कर 1.44 लाख करोड़ रुपये (आवंटन रद्द किए बिना) तक पहुंच जाएगा; वहीं दूसरी ओर, आवश्यक अनुमति

मिलने के बाद सभी कोयला ब्लॉक चालू होने पर कोयले के उत्पादन में काफी वृद्धि होगी।

(2) कोयला ब्लॉकों को रद्द करने से (कोयले के निष्कर्षण और प्रभावी उपयोग की) प्रक्रिया लगभग 7 से 8 साल पीछे चली जाएगी: यह प्रस्तुत किया गया था कि कोयला ब्लॉकों की नीलामी में कम से कम 1-2 साल लगेंगे और पिछले अनुभव से, यह बोलियों या उचित भागीदारी की कमी के कारण नीलामी सफल होने की संभावना नहीं है; नीलाम किए गए कोयला ब्लॉकों को चालू करने में कम से कम 5-6 साल लगेंगे; किसी भी स्थिति में (कोयला मंत्रालय द्वारा आवंटन पत्रों में दी गई समय-सीमा के आधार पर) एक खुली खदान को विकसित करने में 36-42 महीने लगेंगे और एक भूमिगत खदान को विकसित करने में लगभग 48-54 महीने लगेंगे; और विभिन्न मंजूरी प्राप्त करने के बाद अंतिम उपयोग वाले संयंत्रों को चालू करने में कम से कम 3-4 साल लगेंगे।

(3) यदि कोयला ब्लॉक रद्द नहीं किए जाते हैं, तो आवंटी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में अपना योगदान जारी रख सकते हैं: यह एक सकारात्मक नोट पर प्रस्तुत किया गया था कि आवंटियों ने सड़क, रेल लिंक जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश किया है आदि क्योंकि उन्हें आवंटित कोयला ब्लॉक उन क्षेत्रों में थे जहां सीआईएल को निवेश करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी; आवंटियों ने अन्य बुनियादी ढांचे जैसे स्कूल, अस्पताल, स्वच्छ और पीने योग्य पानी की सुविधाएं, आवासीय कॉलोनियां, सामुदायिक केंद्र, खेल का मैदान आदि स्थापित करने और नौकरी के अवसर पैदा करने में भारी निवेश किया है; कोयला ब्लॉक आवंटियों द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों और रॉयल्टी, उपकर आदि के रूप में हजारों करोड़

रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है; और यदि कोयला ब्लॉक रद्द कर दिए गए, तो आवंटियों द्वारा शुरू की गई विकास गतिविधियां रुक जाएंगी।

(4) कई आवंटियों की अपनी विशिष्ट समस्याएं हैं जिनकी जमीनी हकीकत के साथ जांच की जानी चाहिए: यह प्रस्तुत किया गया कि कोयला ब्लॉकों के विकास में देरी के लिए आवंटियां जिम्मेदार नहीं हैं जो वास्तव में स्क्रीनिंग कमेटी की गलतियों के शिकार है; देरी विभिन्न कारणों से होती है जैसे कि पर्यावरण और वन मंत्रालय और कोयला मंत्रालय की ओर से प्रशासनिक देरी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा समय पर सहमति नहीं दी गई, न्यायालय के आदेश, कुछ क्षेत्रों में नक्सली मुद्दे, राज्य सरकारों का निर्देश कि खनन पट्टा निष्पादित नहीं किया जाना चाहिए, 'गो/नो गो' क्षेत्रों का परिचय या क़ानून की अनुमति आदि; इस न्यायालय ने समाज परिवर्तन समुदाय बनाम कर्नाटक राज्य मामले में 1 सितंबर, 2014 को पारित एक आदेश में मंजूरी देने में प्रशासनिक देरी को चुपचाप स्वीकार किया है; इस न्यायालय के लिए उचित कार्रवाई यह होगी कि वह प्रत्येक व्यक्तिगत आवंटन के विशिष्ट तथ्यों की जांच के लिए एक समिति नियुक्त करे।

(5) 295/- प्रति मीट्रिक टन निकाले गए कोयले (जुर्माना के रूप में वर्णित) की अतिरिक्त लेवी अनुचित है: सरकारी खजाने को रूपये 295/- प्रति मीट्रिक टन निकाले गए कोयले की सीमा तक राजस्व की हानि का आंकड़े को सीएजी की रिपोर्ट से उधार लिया गया है, जिस रिपोर्ट पर भारत सरकार ने आपत्ति जताई है और सार्वजनिक उपक्रमों पर संसदीय समिति के समक्ष विचाराधीन है; रिपोर्ट में स्वयं सुझाव दिया गया था कि वित्तीय लाभ का केवल एक हिस्सा ही राष्ट्रीय खजाने में जमा हो सकता था, भारत सरकार ने रुपये 295/- प्रति मीट्रिक टन का आंकड़ा सुझाते समय अपना दिमाग नहीं लगाया है और इसने केवल वर्ष 2010-11 के लिए सीआईएल द्वारा दिए गए

कोयले की औसत कीमत (1028/- रुपये प्रति मीट्रिक टन) पर विचार किया है और इसे पहले के वित्तीय वर्षों के लिए नहीं अपनाया जा सकता है; आवंटित ब्लॉकों से निकाला गया कोयला निम्न गुणवत्ता का है और उसका बिक्री मूल्य सीआईएल के औसत बिक्री मूल्य से बहुत कम है; सीएजी ने कथित वित्तीय घाटे की गणना करते समय भूमिगत खदानों पर विचार नहीं किया है; सीआईएल के लिए कोयले के उत्पादन की लागत कम है क्योंकि निजी क्षेत्र को आवंटित खदानों की तुलना में सीआईएल के पास आर्थिक रूप से व्यवहार्य खदानें हैं जिनमें बुनियादी ढांचे की कमी है और कई अन्य समस्याएं हैं; और जुर्माना पूर्वव्यापी प्रभाव से नहीं लगाया जा सकता क्योंकि आवंटियों द्वारा निकाले गए कोयले का उपयोग पहले ही बिजली, स्टील, सीमेंट आदि के उत्पादन के लिए किया जा चुका है।

16. अंत में, श्री वेणुगोपाल ने अशोक हुर्रे बनाम रूपा अशोक हुर्रे पर भरोसा करते हुए कहा कि कि आबंटियों को उनके कोयला ब्लॉकों को रद्द करने से पहले प्राकृतिक न्याय के स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार सुनवाई का अधिकार है क्योंकि रद्दीकरण उनके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। रिपोर्ट के पैराग्राफ 51 पर भरोसा किया गया और यह इस प्रकार है:

"फिर भी, हम सोचते हैं कि एक याचिकाकर्ता राहत न्याय के दायित्व के कारण हकदार है यदि वह (1) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन स्थापित करता है, जिसमें वह वाद का पक्षकार नहीं था, लेकिन फैसले ने उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला या, यदि वह वाद का एक पक्षकार था, उसे कार्यवाही की सूचना नहीं दी गई और मामला ऐसे आगे बढ़ा जैसे कि उसे सूचना थी, और (2) जहां कार्यवाही में एक विद्वान न्यायाधीश विषय-वस्तु या पक्षकार पूर्वाग्रह

की आशंका की गुंजाईश दे रही है, और निर्णय याचिकाकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।"

17. स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री हरीश साल्वे ने आम तौर पर श्री वेणुगोपाल द्वारा की गई दलीलों का समर्थन किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस न्यायालय के लिए अपनाए जाने वाला अधिक उपयुक्त रास्ता प्रत्येक व्यक्तिगत आवंटन की जांच करने और प्रत्येक आवंटी के विशिष्ट तथ्यों पर विचार करने के लिए विशेषज्ञों सहित तीन व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त करना होगा और इस न्यायालय को रिपोर्ट करना होगा कि कोयला ब्लॉक आवंटन किया रद्द किया जाना चाहिए या नहीं।

18. विद्वान वकील ने प्रत्येक आवंटी को सुनवाई की अनुमति देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया और नेशनल टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन बनाम पी.आर. रामकृष्ण के एक अंश का हवाला दिया, जिसमें संविधान पीठ ने रिपोर्ट के पैराग्राफ 16 में प्राकृतिक न्याय के महत्व पर जोर दिया था। निम्नलिखित अनुच्छेद पर विशेष बल दिया गया:

> "...यह निश्चित रूप से इस आधार पर प्राकृतिक न्याय से इनकार करना न्याय का उपहास होगा कि अदालतें बेहतर जानती हैं। कुछ क्षेत्रों में प्राकृतिक न्याय के बारे में एक अजीब और आश्चर्यजनक गलत धारणा है, कि यह विशेष रूप से एक प्रशासनिक कानून का सिद्धांत है। यह नहीं है। यह सबसे पहले एक सार्वभौमिक सिद्धांत है और इसलिए, प्रशासनिक कानून का एक नियम है। यह न्यायिक प्रक्रिया का वह हिस्सा है जिसे इसकी सार्वभौमिकता के कारण प्रशासनिक प्रक्रिया में आयात किया जाता है। "यह न्याय की अधिकांश प्रणालियों का सार है - निश्चित रूप से एंग्लो-सैक्सन प्रणाली का कि मुकदमेबाजी में निर्णय से पहले विवाद के दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए।

'ऑडी अल्टरम पार्टेम' सेंट ऑगस्टीन का सूत्र था जिसे न्यायालय द्वारा अपनाया गया था ऐसे समय में जब लैटिन मैक्सिम्स फैशनेबल थे"। "ऑडी अल्टरम पार्टेम उतना ही अफ़्रीकी का सिद्धांत है, जितना कि यह अंग्रेजी कानूनी प्रक्रिया का है: एक लोकप्रिय योरूबा कहावत है 'दुष्ट और अधर्मी वह है जो केवल एक पक्ष की गवाही पर मामले का फैसला करता है" (टी.ओ. एलियास: द अफ्रीकी प्रथागत कानून की प्रकृति)। प्रशासकों से भी अधिक न्यायालयों को प्राकृतिक न्याय का पालन करना चाहिए।"

19. श्री साल्वे ने यह तर्क देने के लिए प्रशासनिक कानूनों के एक अंश का भी उल्लेख किया कि कानूनी सापेक्षता के सिद्धांत को न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि "कानून को उन मामलों में उचित और उचित रूप से संचालित किया जा सके जहां अधिकारातीत सिद्धांत, कठोरता से लागू करने पर अस्वीकार्य परिणाम मिलेंगे।"

20. दुर्भाग्य से, विद्वान वकील द्वारा उद्धृत मार्ग की प्रासंगिकता को देखना मुश्किल है क्योंकि यह एक अधिनियम या आदेश की शून्यता और शून्यता से संबंधित है जो अधिकारातीत है। लागू सिद्धांत पूरी तरह से अलग हैं और हम ऐसे किसी मामले से नहीं निपट रहे हैं। डॉ. ए.एम. द्वारा उद्धृत शीला बरसे बनाम भारत संघ के एक अंश का संदर्भ लेना अधिक उपयुक्त होगा। सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता (इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से उपस्थित) जिसमें इस न्यायालय ने कहा कि भविष्य महत्वपूर्ण है (और हम इसी पर विचार कर रहे हैं)। इस न्यायालय ने कहा:

"फिर से, दी जाने वाली राहत भविष्य को देखती है और आम तौर पर, क्षतिपूर्ति के बजाय सुधारात्मक होती है, जो कभी-कभी होती भी है। राहत का पैटर्न

आवश्यक रूप से दावा किए गए या पाए गए अधिकारों से तार्किक रूप से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि, अदालत केवल एक निष्क्रिय, उदासीन अंपायर या दर्शक नहीं है, बल्कि कार्यवाहियो के संगठन, राहत के ढांचे आदि की जिम्मेदारी के साथ इसकी अधिक गतिशील और सकारात्मक भूमिका है और - यह महत्वपूर्ण है – इसके कार्यान्वयन की निगरानी भी कर रहे है। न्यायालय विशेषज्ञ पैनलो, आयुक्तो, सहायक समिति, एमीसी आदि की सहायता लेने का हकदार है और अक्सर लेता है। जिम्मेदारियों की यह विस्तृत श्रृंखला आवश्यक रूप से पक्षकारो, विषय वस्तु और प्रक्रिया पर नियंत्रण के उच्च उपाय का तात्पर्य करती है। वास्तव में जैसा कि राहत सकारात्मक और सकारात्मक कार्रवाई का तात्पर्य है, निर्णय "एक-बारगी" निर्धारण नहीं हैं, बल्कि निरंतर निहितार्थ हैं। समाधान थोपा हुआ, बातचीत से या अर्ध-बातचीत दोनों तरह से किया जाता है।

21. डॉ. ए.एम. सिंघवी ने एक नोट भी प्रस्तुत किया जो अनिवार्य रूप से और पर्याप्त रूप से श्री वेणुगोपाल द्वारा की गई कुछ दलीलों को दोहराता है। इसलिए, उन अनुरोधों को दोहराना आवश्यक नहीं है। उन्होंने ओंकार लाल बजाज बनाम भारत संघ का भी हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों के लिए डीलरशिप के स्पष्ट रूप से दागी आवंटन के मामले में, इस न्यायालय ने एक समिति नियुक्त करने की आवश्यकता महसूस की और इसलिए हमें सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की एक समिति कोयला ब्लॉक आवंटन के प्रत्येक व्यक्तिगत मामले की जांच करने के लिये नियुक्त करनी चाहिए।

22. हस्तक्षेपकर्ताओं में से एक की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. राजीव धवन ने आवंटियों के पक्ष में किए गए आवंटन को रद्द करने से पहले प्राकृतिक न्याय

के सिद्धांतों को लागू करने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए चिंगलपुट बॉटलर्स बनाम मैजेस्टिक बॉटलिंग कंपनी का हवाला दिया।

23. अन्य विद्वान वकीलों ने, राज्य सरकारों सहित अपने संबंधित ग्राहकों के मामले के तथ्यों के आधार पर थोड़े बदलाव और जोर के साथ, कमोबेश दोहराए और पुन:कथन किये ।

24. विभिन्न विद्वान वकीलों द्वारा की गई दलीलों के जवाब में, विद्वान अटॉर्नी जनरल द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि कोयला ब्लॉक आवंटन रद्द करने के आर्थिक निहितार्थ या परिणाम और इसके संभावित प्रतिकूल प्रभाव सहित ऊपर उल्लिखित सभी पहलू शामिल हैं। अन्य सामाजिक-आर्थिक कारकों को भी ध्यान में रखा गया है और इसके बाद ही भारत संघ द्वारा हलफनामा दायर किया गया है, जिसे उन्होंने अपने शुरुआती संबोधन में समझाया है। दूसरे शब्दों में, यदि आवश्यकता पड़ी तो भारत संघ सभी कोयला ब्लॉकों को रद्द करने के परिणामों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और आगे बढ़ने का इच्छुक है।

25. विद्वान अटॉर्नी जनरल ने विद्वान वकीलों द्वारा प्रस्तावित किसी भी समिति की स्थापना का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से और जोरदार ढंग से कहा कि कोयला ब्लॉकों को रद्द करने के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार को मामले को आगे बढ़ाने में कोई कठिनाई नहीं है।

26. आवंटियों के लिए विद्वान वकीलों ने अनिवार्य रूप से दो तर्क उठाए हैं। सबसे पहले, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार कोयला ब्लॉक आवंटन रद्द करने से पहले उनकी बात सुनी जानी चाहिए। दूसरे, हमें प्रत्येक व्यक्तिगत मामले पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त करनी चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कोयला ब्लॉक आवंटन रद्द किया जाना चाहिए या नहीं।

27. जहां तक दूसरे तर्क का सवाल है, विद्वान अटॉर्नी जनरल ने इसका कड़ा विरोध किया है और हमें लगता है कि वह ऐसा करने में सही हैं। यह निर्णय किसी व्यक्तिगत मामले से संबंधित नहीं था। इसने केवल कोयला ब्लॉकों के आवंटन की प्रक्रिया पर विचार किया और इसे अवैध और मनमाना पाया। किसी समिति की नियुक्ति के माध्यम से आवंटन की प्रक्रिया को दोबारा शुरू नहीं किया जा सकता है। यह वस्तुतः फैसले को रद्द करने जैसा होगा। यह प्रक्रिया एक सतत सूत्र है जो सभी आवंटनो के माध्यम से चलती है। चूँकि यह घातक रूप से त्रुटिपूर्ण था, त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया के लाभार्थियों को इसके परिणाम भुगतने होंगे और एक समिति की नियुक्ति वास्तव में निर्णय की शुद्धता की जांच करने के लिए एक निकाय को अनुमति देने के समान होगी। यह स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है.

28. यह सच है कि इस न्यायालय ने कई मामलों में किसी न किसी समिति की सहायता ली है, लेकिन वहां जांच की आवश्यकता थी और यह न्यायालय स्पष्ट रूप से ऐसी कोई जांच करने की स्थिति में नहीं था। उदाहरण के लिए, ओंकार लाल बजाज में ऐसा हुआ था। वर्तमान मामले में ऐसा कोई अवसर या स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है कि किसी समिति की नियुक्ति की आवश्यकता पड़े। इसलिए समिति नियुक्त करने का सवाल ही नहीं उठता.

29. पहला विवाद प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की प्रयोज्यता से संबंधित है। जहां तक इसका सवाल है, इसे निर्णय में (पैराग्राफ 11 में) विशेष रूप से निम्नलिखित प्रभाव से दर्ज किया गया है:

> "तीन एसोसिएशन, अर्थात, कोल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपने हस्तक्षेप के लिए आवेदन किया है, जिसमें कहा गया है कि ये

एसोसिएशन बड़ी संख्या में आवंटियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। तदनुसार, एम के के वेणुगोपाल, वरिष्ठ वकील कोल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन और श्री हरीश एन साल्व विद्वान वरिष्ठ वकील को स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और इंडिपेंडेंट पॉव प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से सुना गया। उन्होंने 09.01.2014 को बहस शुरू की, जो 15.01.20 तक जारी रही। और 16.01.2014 को संपन्न हुई।"

30. इसलिए, यह कहना गलत है कि कोयला ब्लॉकों के आवंटित लाभार्थियों के थोक (यदि सभी नहीं) का प्रतिनिधित्व करने वाली इन संस्थाओं की बात नहीं सुनी गई। उन्होने मामले में किसी भी अन्य पक्ष की तरह वाद मे अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और उसके बाद निर्णय सुनाया।

31. इसी प्रकार, कई राज्यों को भी सुना गया जैसा कि फैसले के पैराग्राफ 10 में दर्ज किया गया है। इस संबंध में कहा गया:

"05.12.2013 को बहस फिर से शुरू हुई। उस दिन, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों की दलीलें पूरी हो गईं और मामले की तारीख 08.01.2014 तय की गई। 08.01.2014 को महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों की ओर से दलीलें पूर्ण हुईं और मामले को दिनांक 09.01.2014 के लिए नियत किया गया। उस दिन, विद्वान अटॉर्नी जनरल की दलीलें समाप्त हो गईं।"

32. वास्तव में, प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना वाले सभी पक्षों को सुनने का मौका दिया गया। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हुए भी यथार्थवादी एवं व्यावहारिक रूप से लागू होने चाहिए।

33. शीला बरसे में यह देखा गया था, और हम उस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, कि किसी मामले में दी जाने वाली राहत हमेशा भविष्य को देखती है। यह आम तौर पर सुधारात्मक है और कुछ मामलों में यह प्रतिपूरक है। वर्तमान मामला शीला बरसे में उल्लिखित सभी तीन तत्वों को अपने दायरे में लेता है। हमारे फैसले ने कोयला ब्लॉकों के आवंटन में अवैधता और मनमानी को उजागर किया और इन "परिणामात्मक कार्यवाहियों" का उद्देश्य भारत संघ द्वारा की गई गलती को सुधारना है; ये कार्यवाहियाँ गलत को उजागर करके भविष्य की ओर देखती हैं, यह अपेक्षा की जाती है कि सरकार देश के प्राकृतिक संसाधनों के साथ इस तरह व्यवहार नहीं करेगी जैसे कि वे कुछ व्यक्तियों के हैं जो उन्हें अपनी इच्छानुसार बर्बाद कर सकते हैं; विद्वान अटॉर्नी जनरल द्वारा सुझाए गए तरीके से, ये कार्यवाहियाँ सरकारी खजाने को हुए नुकसान की भरपाई भी कर सकती हैं, और जिस पर अब हम विचार करने का प्रस्ताव रखते हैं।

34. कोयला ब्लॉक आवंटन की दो श्रेणियां हैं: पहली श्रेणी अनुबंध 1 और अनुबंध 2 में उल्लिखित आवंटन के अलावा अन्य आवंटन हैं; दूसरी श्रेणी अनुलग्नक 1 और अनुलग्नक 2 में उल्लिखित 46 कोयला ब्लॉक है, जिन्हें संभवतः कुछ नियमो और शर्तो पर रद्द होने से "बचाया" जा सकता है, जैसा कि विद्वान अटॉर्नी जनरल द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

35. जहां तक कोयला ब्लॉक आवंटन की पहली श्रेणी का सवाल है, उन्हें रद्द किया जाना चाहिए (निर्णय में उल्लिखित को छोड़कर)। उन्हें रद्दीकरण से "बचाने" का कोई कारण नहीं है। आवंटन अवैध और मनमाने हैं; आवंटियों ने अभी तक कोई खनन पट्टा नहीं लिया है और उन्होंने अभी तक उत्पादन भी शुरू नहीं किया है। चाहे वे 95% तैयार हों या 92% तैयार हों या 90% उत्पादन के लिए तैयार हों, (जैसा कि

कुछ विद्वान वकील तर्क देते हैं) पूरी तरह से अप्रासंगिक है। उनका आवंटन अवैध और मनमाना था, जैसा कि पहले ही माना जा चुका है, और इसलिए हम इन सभी आवंटनों को रद्द करते हैं।

36. विद्वान अटॉर्नी जनरल ने 46 कोयला ब्लॉकों की पहचान की जिन्हें गिलोटिन से "बचाया" जा सकता है, क्योंकि उनमें से सभी ने उत्पादन शुरू कर दिया है या उत्पादन शुरू करने के कगार पर हैं। चूंकि ये आवंटन भी अवैध और मनमाने हैं इसलिए इन्हें रद्द भी किया जा सकता है। हालाँकि, अनुलग्नक 1 में तीन कोयला ब्लॉकों के आवंटन में कोई गड़बड़ी नहीं है और वे सासन पावर लिमिटेड (यूएमपीपी) को आवंटित मोहर और मोहर अमरोली एक्सटेंशन और केंद्र सरकार की सार्वजनिक कंपनी तासरा (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को आवंटित) हैं, केंद्रीय सरकार लोक क्षेत्र का उपक्रम जिसका कोई संयुक्त उद्यम नहीं है)।

जहां तक अनुबंध 2 में उल्लिखित 6 कोयला ब्लॉकों का सवाल है, आवंटितकर्ताओं ने अभी तक उत्पादन शुरू नहीं किया है। जहां तक परिणामों का सवाल है, वे अलग या बेहतर स्तर पर नहीं खड़े हैं। ये आवंटन भी रद्द किये जा सकते हैं। पकरी बरवाडीह कोयला ब्लॉक (नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) को आवंटित, केंद्र सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम होने के कारण इसका कोई संयुक्त उद्यम नहीं है) का आवंटन रद्द किये जाने को उत्तरदायी नहीं है।

37. यूएमपीपी को किए गए उपरोक्त दो आवंटन और और केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को किए गए दो आवंटन, जिनमें ऊपर उल्लिखित कोई संयुक्त उद्यम नहीं है, अनुबंध 1 और अनुबंध 2 में उल्लिखित अन्य सभी आवंटन रद्द कर दिए गए हैं।

38. विद्वान अटॉर्नी जनरल द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि कोयला ब्लॉक आवंटन रद्द होने पर, सीआईएल को अपने मामलों का प्रबंधन करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी। केंद्र सरकार आगे बढ़ने की इच्छुक है लेकिन उभरती स्थिति को संभालने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार, कोयला ब्लॉकों के रद्द होने पर अपने मामलों का प्रबंधन करने के लिए आवंटियों को राहत देने का समय भी दिया जाना आवश्यक है।

39. प्रस्तुत तर्को के मद्देनजर, हालांकि हमने इन 46 कोयला ब्लॉकों में से 42 के आवंटन को रद्द कर दिया है, हम यह स्पष्ट करते हैं कि रद्दीकरण आज से छह महीने बाद ही प्रभावी होगा, जो 31 मार्च, 2015 से प्रभावी है। छह महीने की यह अवधि इसलिए दी जा रही है क्योंकि विद्वान अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि केंद्र सरकार और सीआईएल को बदली हुई स्थिति के साथ तालमेल बिठाने और आगे बढ़ने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी। यह अवधि कोयला ब्लॉक आवंटियों को अपने मामलों को समायोजित करने और प्रबंधित करने के लिए पर्याप्त समय भी देगी। जैसा कि विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है, सीआईएल अक्षम है और चुनौती स्वीकार करने में असमर्थ है, यह कोई मुद्दा ही नहीं है। जैसा कि विद्वान अटॉर्नी जनरल ने कहा है, केंद्र सरकार आश्वस्त है कि सीआईएल इस कमी को पूरा कर सकती है और चीजों को आगे ले जा सकती है।

40. रद्दीकरण को स्थगित करने के अनुरोध के अलावा, हम विद्वान अटॉर्नी जनरल की इस दलील को भी स्वीकार करते हैं कि फैसले के दायरे में आने वाले कोयला ब्लॉकों और इस आदेश के दायरे में आने वाले चार कोयला ब्लॉकों के अलावा अन्य कोयला ब्लॉकों के आवंटियों को एक 295/- रूपये प्रति मीट्रिक टन कोयला निकाले जाने के लिये अतिरिक्त लेवी के रूप में राशि का भुगतान करना होगा। यह

क्षतिपूर्ति राशि सीएजी द्वारा किये गये आकलन पर आधारित है। यह अच्छी तरह से हो सकता है कि भूमिगत खदान से कोयला निकालने की लागत पर सीएजी ने विचार नहीं किया है, लेकिन इस प्रकृति के मामलों में नुकसान की मात्रा निर्धारित करने वाले किसी भी गणितीय रूप से स्वीकार्य आंकड़े पर पहुंचना मुश्किल है। कोयले का अंदाजन नुकसान रुपये 295/- प्रति मीट्रिक टन है, इसलिये इन प्रकरणो के उददेश्यो के लिये स्वीकार्य है। इस आधार पर मुआवजे का भुगतान तीन महीने की अवधि के भीतर और किसी भी स्थिति में 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले किया जाना चाहिए। इसके बाद 31 मार्च, 2015 तक निकाले गए कोयले पर भी रुपये 295/- प्रति मीट्रिक टन की अतिरिक्त लेवी लगेगी।

41. यह स्पष्ट किया जाता है कि विद्वान अटॉर्नी जनरल द्वारा पहचाने गए 46 में से 12 कोयला ब्लॉकों के आवंटन (और उस मामले के लिए किसी अन्य आवंटी के खिलाफ) के संबंध में सीबीआई द्वारा जांच जारी रहेगी और इसे तार्किक निष्कर्ष तक ले जाया जाएगा। कहने की जरूरत नहीं है कि इस आदेश की टिप्पणियों और निष्कर्षों का लंबित जांचों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

निधि जैन

परिणामी कार्यवाहियो में आदेश पारित किया गया।

अनुलग्नक - 1

उत्पादन मे आ चुके 40 कोयला ब्लॉको का विवरण -

क्र.सं.	कोयला ब्लॉक का नाम	आवंटिती कंपनी का नाम
1	गारे पालमा IV/4	जयास्वल नीको लिमिटेड
2	चोटिया	प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड
3	नामचिक नामफुक	अरूणाचल प्रदेश माईनिंग कॉर्पोरेशन
4-5	गारे पालमा IV/2 ओर 3	जेएसपीएल
6	बेलगांव	सनफलैग आयरन एंड स्टील लिमिटेड
7-12	बर्नज 1- IV, किरोनी और मनोरादीप	कमाटका पावर कॉर्पो. लिमि.
13	कथूटिया	उषा मार्टिन लिमिटेड
14	पर्बतपुर	इलैक्ट्रोस्टील कास्टिंग्स लिमि.
15	गारेपालमा IV/7	आरएपीएल, अब सारदा एनर्जी लिमि.
16	बरजोरे	डब्लूओपीडीएसएल
17	तारा, ईस्ट	डब्लूबीएसईबी
18	तारा वैस्ट	डब्लूबीपीडीसीएल
19	गारे पालमा IV/1	जिंदल पावर लिमि.
20	सरशतली	सीईएससी
21	तालाबीरा-1	हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमि.
22-23	गोटीटोरिया ईस्ट एंड वैस्ट	बीएलए इंडस्ट्रीज
24	गारे पालमा IV/5	मॉनेज इस्पात लिमि.

25	पचवारा सैंट्रल	पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड
26	तासरा	स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमि.
27	बरजोरा नॉर्थ	डीवीसी
28	मार्की मंगली -।	बी एस इस्पात
29-30	मार्की मंगली-।।। मार्की मंगली-।।	
31	ट्रांस दामोदर	डब्लूबीएमटीसीडीएल
32-33	मोहेर एंड मोहेर अमलोरी एक्सटेंशन	सासन पावर लिमि.
34	अर्धग्राम	सोवा इस्पातल लिमि. एंड जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमि.
35-36	पारसा ईस्ट एंड कांता बासन	आरआरवीयूएन लिमि.
37-38	गंगारामचक एंड गंगारामचक भादुलिया	डब्लूबीपीडीसीएल
39	अमेलिया नॉर्थ	एमपीएसएमडीसी लिमि.
40	पचवारा नॉर्थ	डब्लूबीपीडीसीएल

अनुलग्नक - 2

कोयला ब्लॉकों का विवरण, जो 2014-15 के उत्पादन के दौरान आने की संभावना है।

ब्लॉक की क्र.सं.	कंपनी का नाम	कोयला ब्लॉक का नाम
1.	जीवीके पावर, गोविंदवाल साहब	तोकीसुद नॉर्थ

2.	डीवीसी	खागरा जॉयदेव
3.	प्रिसम सीमेंट	साईल घोगरी
4.	जयप्रकाश एसोसियेटस लिमि.	मंडिया नॉर्थ
5.	एमपीएसएमसीएल	बीचरपुर
6.	एनटीपीसी	पकरी बरवडिया

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यो के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।